कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन की हालत पतली

तमिलनाडु चुनाव

प्रभात कुमार रॉय

विगत 40 वर्षों से तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास वस्तुतः सर्वविदित उक्ति को साकार रूप से चरितार्थ करता रहा है कि व्यवहारिक राजनीति में राजसत्ता हथियाने के कुटिल खेल के तहत न तो कभी स्थायी तौर पर दोस्त होते हैं और न ही कभी स्थायी तौर पर दुश्मन। वर्ष 2011 में तमिलनाडु में विधान सभा के लिए आयोजित होने वाले आम चुनाव में सन् 2004 से केंद्रीय राजसत्ता में नेशनल कांग्रेस की साझीदार और सहयोगी बनी रही द्रविड़ मुनेत्र कड़घम (डीएमके) पार्टी के मध्य सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त तकरार सामने आ गई और नौबत यहां तक आ गई कि डीएमके ने केंद्रीय हुकूमत के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस (यूपीए) से अलग होने का बाकायदा ऐलान कर दिया। डीएमके पार्टी के केंद्रीय मंत्रीगणों ने प्रधानमंत्री महोदय को अपने त्यागपत्र पेश कर दिए। कांग्रेस-डीएमके का ध्वस्त होने के कगार तक पंहुचा एलाइंस, कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक समझदारी और सक्रियता के कारण आखिरकार बचा लिया गया।

वर्ष 2006 में तमिलनाडु के विगत विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके पार्टी के साथ चुनावी

एलाइंस करके विधानसभा की 48 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 सीटों पर अपनी विजय दर्ज कराई थी। इस बार 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर अड़ा हुआ था। अतः नेशनल कांग्रेस और डीएमके मध्य सीटों के बंटवारे के प्रश्न पर डेडलॉक हो गया और सीटों के बंटवारे पर जारी तकरार केंद्रीय हुकूमत से डीएमके के अलगाव तक आ गई। प्रणब मुखर्जी की पहल पर अंततः डीएमके का नेतृत्व कांग्रेस के लिए विधान सभा की 51 सीटें प्रदान करने के लिए तैयार हो गया और मनमोहन सिंह सरकार पर आया संकट समाप्त हो गया।

दरअसल तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ ताकतवर नेता ही राहुल गांधी की सोच और समझदारी के कायल होकर वहां अकेले चुनाव में उतरने का मन बना रहे थे। कांग्रेस के इन्हीं प्रांतीय नेताओं ने डीएमके साथ चुनावी एलाइंस तोड़ने की नीयत से 75 सीटें कांग्रेस के लिए दरयाफ्त की। कांग्रेस के कुछ शीर्ष केंद्रीय नेतागण सोनिया गांधी को समझा रहे थे कि 2 जी स्पेक्ट्रम स्कैंडल के कलंक से पार्टी की जान छुड़ाना चाहती है तो एकदम उचित अवसर है कि कांग्रेस अभी इसी वक्त डीएमके से अपना एलाइंस तोड़ दे। दूसरी ओर प्रणब मुखर्जी सरीखे नेता रहे जोकि सोनिया गांधी के समक्ष तर्क दे रहे थे कि कांग्रेस यदि डीएमके से एलाइंस तोड़कर अपने बलबूते पर चुनाव में उतरेगी तो बिहार विधान सभा चुनाव से भी अधिक खराब दुर्गति ही हो जाएगी। अंततः प्रणब दा के तर्क प्रबल सिद्ध हुए और कांग्रेस का नेतृत्व मात्र तीन सीटों की बढ़ोत्तरी पर डीएमके साथ एलाइंस जारी रखने को रजामंद हो गया।

कांग्रेस और डीएमके के मध्य बनते और बिगड़ते राजनीतिक रिश्तों की बानगी से ही तमिलनाडु की राजनीति समझ आती है। तमिलनाडु में कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व को अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़घम ने निर्णायक तौर पर ललकारा और ध्वस्त कर दिखाया। 1967 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को पराजित करके डीएमके ने तमिलनाडु में अपनी प्रथम सरकार तशकील की। 1971 के आम चुनाव से पहले ही 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। तमिलनाडु में एक ओर कांग्रेस के कद्दावर राष्ट्रीय नेता के. कामराज थे और दूसरी ओर इंदिरा गांधी के वफादार सी. सुब्रहमण्यम थे। नेशनल कांग्रेस के साथ डीएमके का पहला चुनावी एलाइंस 1971 के आम चुनाव में हुआ और इस गठबंधन ने विरोधियों का सफाया कर दिया। नौ वर्षों के अंतराल के बाद 1980 के मध्यावधि चुनाव में फिर से कांग्रेस-डीएमके एलाइंस वजूद में आया और इसने 1971 के आम चुनाव की जबरदस्त कामयाबी की दास्तान पुनः दोहरा दी। दो दशक के बाद 2004 में कांग्रेस और डीएमके पार्टी का चुनावी गठजोड़ फिर कायम हुआ और विधानसभा ने प्रांत की समस्त लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की।

2004 में कायम हुआ कांग्रेस-डीएमके एलाइंस, 2006 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव में कायम बना रहा और इसने कामयाबी के जबरदस्त झंडे गाड़ दिए। 2011 के विधान सभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस-डीएमके एलाइंस की हालत पतली बनी हुई है, क्योंकि डीएमके के नेता और पूर्व केंद्रीय संचारमंत्री ए. राजा भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम के तहत जेल में हैं। राज्य में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर हैं। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की लोकप्रियता में गंभीर गिरावट दर्ज की गई है।

तमिल राजनीति हालांकि भावनात्मक तौर पर जातिय और सांस्कृतिक समीकरणों से संचालित होती रही है और अनेक दशक से यहां द्रविड बनाम आर्य राजनीति का बोलबाला बना रहा है। फिर भी ऐसे ताकतवर राजनीतिक तत्व तमिलनाडु में सदैव विद्यमान रहे हैं, जोकि प्रांत के आर्थिक विकास, जनमानस के भयावह आर्थिक शोषण एवं सरकारी भ्रष्टाचार को तमिल राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने में जुटे हुए हैं। इन सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए यह बात पुख्ता तौर कही जा सकती है कि 2011 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस-डीएमके एलाइंस धराशायी होगा और एआईडीएमके एलाइंस कामयाब होकर उभरेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार है)

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission